>

Title: Need to set up a National Gramin Bank and give adequate decision making power and facilities to the existing Rural Banks.

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : महोदय, देश में ग्रामीण बैंकों ने किसानों के विकास व उनके हितों में जो भूमिका निभाई है, उसके मुकाबले राष्ट्रीयकृत बैंक काफी पीछे हैं। परन्तु आजादी के 60 वर्ष बाद भी ग्रामीण बैंकों को अपने प्रायोजन बैंक के निर्णयों के अंतर्गत ही किसानों के हितों के संबंध में कोई निर्णय लेना होता है। इतना ही नहीं सरकार द्वारा ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुकाबले पेंशन, भत्ते व अन्य सुविधाएं नहीं दी जाती जिससे ग्रामीण बैंक कर्मचारी अपने को उत्पीड़ित समझते हैं। इसका उनके कार्यों पर भी असर पड़ता है।

आज देश में भूख, कुपोषण, बेरोजगारी, साहूकारों के कर्ज से दबे किसानों द्वारा खुदकुशी निरंतर बढ़ रही है, जिससे सरकार चिंतित तो है पर कोई संतोषजनक और ठोस निर्णय, जो किसान हितैषी और जिससे किसानों की समस्या को दूर किया जा सके, नहीं ले पाती। सबसे ज्यादा कर्ज किसानों को ग्रामीण बैंक ही उपलब्ध करवाते हैं, वो भी किसानों की सुविधाओं के अनुसार और ब्याज दर भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुकाबले कम दर पर। परंतु, अत्यधिक चिंता की बात है कि आज ग्रामीण बैंकों की शाखाएं बढ़ने की बजाय कम हो रही हैं।

मेरा सरकार से आग्रह है कि सभी ग्रामीण बैंकों को मिलाकर राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किया जाये। ग्रामीण बैंकों को प्रायोजक बैंक के नियंत्रण से मुक्त कर स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार दिया जाये, पेंशन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें प्रायोजन बैंकों के कर्मचारियों के बराबर किया जाये। नयी भर्ती व्यवस्था व पदोन्नति की व्यवस्था की जाये और नाबार्ड की भूमिका ग्रामीण बैंक के वित्त पोषक प्रबंधन में तेज की जाये।